

वर्श्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024

प्रलमिस के लयि:

अंतरराष्ट्रीय शरम संगठन (ILO), बेरोज़गारी, शरम बाज़ार, G20 देश, अनौपचारिक कारय ।

मेन्स के लयि:

वर्श्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 ।

स्रोत: द हद्वि

चरचा में कयों?

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शरम संगठन (ILO) ने वर्श्व रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 रिपोर्ट जारी की है, जसमें बताया गया है कि वर्श्विक बेरोज़गारी दर वर्ष 2024 में बढ़ने वाली है और बढ़ती असमानताएँ एवं स्थिर उत्पादकता चर्चा का कारण हैं ।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- बगिड़ती आर्थिक स्थितियों के बीच लचीलापन:
 - बगिड़ती आर्थिक स्थितियों के बावजूद, वर्श्विक शरम बाज़ारों ने बेरोज़गारी दर और नौकरियों के अंतर दर (रोज़गार रहति व्यक्तियों की संख्या जो नौकरी खोजने में रुचि रखते हैं) दोनों में सुधार के साथ आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया है ।
- वर्श्विक बेरोज़गारी रुझान:
 - वर्ष 2023 में वर्श्विक बेरोज़गारी दर 5.1% थी, जो वर्ष 2022 की तुलना में मामूली सुधार है ।
 - हालाँकि रिपोर्ट में शरम बाज़ार के बगिड़ते परदृश्य का अनुमान लगाया गया है, वर्ष 2024 में अतिरिक्त 20 लाख शरमकों के नौकरियों की तलाश करने की उम्मीद है, जससे वर्श्विक बेरोज़गारी दर 5.2% तक बढ़ जाएगी ।
- असमान पुनरप्राप्ति:
 - महामारी से उबरना असमान है, नई कमज़ोरियों और कई संकटों के कारण व्यापक सामाजिक न्याय की संभावनाएँ कम हो रही हैं ।
 - बेरोज़गारी दर और नौकरियों के अंतर दर दोनों के संदर्भ में, उच्च एवं नमिन आय वाले देशों के बीच मतभेद बने रहते हैं ।
 - वर्ष 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोज़गारी अंतराल दर 8.2% था जबकि नमिन आय वाले देशों में यह 20.5% थी ।
 - इसी प्रकार वर्ष 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोज़गारी दर 4.5% पर बनी रही जबकि कम आय वाले देशों में यह 5.7% थी ।
- आय असमानता में वृद्धि:
 - आय असमानता में वृद्धि हुई है तथा अधिकांश G20 देशों में प्रयोज्य आय में गरिावट आई है ।
 - वास्तविक प्रयोज्य आय में कमी को कुल मांग तथा अधिक नरितर आर्थिक सुधार के लयि एकनकारात्मक कारक के रूप में देखा जाता है ।
 - प्रयोज्य आय नविल आय प्रदर्शति करती है । यह करों के बाद शेष राशिको संदर्भति करती है ।
- कामकाज़ी गरीबी की स्थिति:
 - वर्ष 2020 के बाद संबद्ध क्षेत्र में तेज़ी से गरिावट के बावजूद अत्यधिक गरीबी में रहने वाले शरमकों की संख्या (करय शक्तिसमता के संदर्भ में प्रतियक्तप्रतदिनि 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम आय) वर्ष 2023 में लगभग 1 मलियिन बढ़ गई ।
 - मध्यम नरिधनता (PPP के संदर्भ में प्रतियक्तप्रतदिनि USD3.65 से कम आय) में रहने वाले शरमकों की संख्या 2023 में 8.4 मलियिन बढ़ गई ।
 - कामकाज़ी गरीबी एक चुनौती के रूप में बनी रहने की संभावना है ।
- अनौपचारिक कारय दरों की स्थिति:
 - अनौपचारिक कारय की दरों में स्थरिता रहने की उम्मीद है जो वर्ष 2024 में वर्श्विक कारयबल का लगभग 58% है ।
- शरम बाज़ार का असंतुलन:
 - महामारी से पहले शरम बाज़ार में भागीदारी की दर की वापसी वभिन्न समूहों के बीच भन्न-भन्न रही है ।
 - महिलाओं की भागीदारी में तेज़ी से वापसी हुई है, परंतु लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है, वर्श्विक उभरते और विकासशील देशों में ।

- युवा बेरोज़गारी दर और **NEET (रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं) श्रेणी उच्च** बनी हुई है, जिससे दीर्घकालिक रोज़गार संभावनाओं के लिये चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं।
- **उत्पादकता में कमी:**
 - महामारी के बाद थोड़े समय के लिये **उत्पादकता** में वृद्धि देखी गई कति **श्रम उत्पादकता पछिले दशक में** देखे गए नमिन स्तर पर लौट आई है।
 - कौशल की कमी और बड़े डिजिटल एकाधिकार के प्रभुत्व सहित बाधाओं के साथ, तकनीकी प्रगति और **बढ़े हुए नविश के बावजूद उत्पादकता वृद्धि धीमी बनी हुई है।**
- **अनश्चिति परदिश्य और संरचनात्मक चिंताएँ:**
 - हाल ही में देखे गए असंतुलन **केवल महामारी का परिणाम मात्र नहीं है बल्कि संरचनात्मक चुनौतियाँ भी** इसका कारण हो सकती हैं। **कार्यबल संबंधी चुनौतियाँ व्यक्तिगत आजीविका और व्यवसाय** दोनों के लिये खतरा पैदा करती हैं।
 - गरिबे जीवन स्तर, **कमजोर उत्पादकता, नरितर मुद्रास्फीति और अधिक असमानता सामाजिक** न्याय तथा सतत् पुनर्प्राप्ति के प्रयासों को क्षीण करती है। रपिर्ट इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- **सकारात्मक वास्तविक मज़दूरी:**
 - **भारत और तुर्की में वास्तविक मज़दूरी अन्य G20 देशों की तुलना में "सकारात्मक" है, लेकिन उपलब्ध डेटा 2021 के सापेक्ष 2022 का संदर्भ देता है।** इसका तात्पर्य यह है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत में वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति से आगे निकलने में कामयाब रही है, जिससे वास्तविक मज़दूरी में सुधार में योगदान मिला है।
 - अन्य G20 देशों में वास्तविक मज़दूरी में गिरावट देखी गई; गिरावट **वशिष रूप से ब्राज़ील (6.9%), इटली (5%) और इंडोनेशिया (3.5%) में** देखी गई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है?

- **परिचय:**
 - इसे वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वरसाय की संधि के हिससे के रूप में बनाया गया था, इस विश्वास को प्रतबिबिति करने के लिये कि सार्वभौमिक तथा स्थायी शांति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।
 - यह वर्ष 1946 में **संयुक्त राष्ट्र** की एक वशिष एजेंसी बन गई।
 - यह एक त्रपिक्षीय संगठन है, जो अपनी तरह का एकमात्र संगठन है जो अपने **कार्यकारी निकायों में सरकारों, नयोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।**
- **सदस्य:**
 - कुल 187 सदस्य देशों के साथ भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।
 - 2020 में भारत ने ILO के **शासी निकाय की अध्यक्षता** ग्रहण की।
- **मुख्यालय:**
 - जनिवा, स्विट्ज़रलैंड
- **पुरस्कार:**
 - वर्ष 1969 में, ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारा और शांति में सुधार करने, श्रमिकों के लिये सभ्य कार्य और न्याय प्रदान करने के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये **नोबेल शांति पुरस्कार** मिला।

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 कसिसे संबंधित हैं? (2018)

- बाल श्रम
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषि प्रथाओं का अनुकूलन
- खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- कार्यस्थल पर लिंग समानता

उत्तर: (a)